

प्रेषक,

विनीता कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक : 15 मई 2008

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के 1 से 10 तक की योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुपालन में समाज कल्याण के शासनादेश संख्या: 226/XVII-3/08-7(17)/2008, दिनांक 30 अप्रैल 2008 जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति कुल रु0. 1,22,09,000.00 (रुपया एक करोड़ बाईस लाख नौ हजार) मात्र की धनराशि समस्त जनपदों को निर्गत की गयी है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष रु0.17,91,000.00 (रुपया सत्रह लाख इकानबे हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के "आयोजनागत पक्ष" में अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं इस निर्देश के साथ आपके निर्वहन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जनपदों को उनकी मांगानुसार वांछित धनराशि निर्गत की जाय:-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास्य के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय।
3. जिला योजना के अंतर्गत वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 267/XXVII(1)/ 2008, दिनांक 27 मार्च 2008 तथा राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 624/जि0यो0/रा0यो0

आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24 मार्च 2008, में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) के आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-17 पर निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अवचनबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाय।
8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें तथा बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाए—
  - (1) प्रत्येक लाभार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान लाभार्थी के डाकघर बचत खाते माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
  - (2) प्रत्येक जनपद के लाभार्थियों की सूची हार्ड एव साफ्ट कापी में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के प्रवर डाकर अधीक्षक/डाकघर अधीक्षक को अग्रिम रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।
  - (3) प्रत्येक जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वांछित धनराशि का एक चैक, जो कि संबंधित जनपद के प्रधान डाकघर के पोस्ट

मास्टर के पक्ष में देय होगा को लाभार्थियों की सूची सहित उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) बैंक प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर लाभार्थी के बचत खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।

(5) दिनांक 15 नवम्बर 2007 को डाक विभाग, उत्तराखण्ड परिमण्डल के साथ किए गए एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

13. इस संबन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ- 00- 800-अन्य व्यय-91-अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1-10 के छात्रों को छात्रवृत्ति-00, के मानक मद 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या: 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च 2008, जिसके द्वारा प्रशासनिक विभाग को वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है, के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विनीता कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या 244/XVII-3/08-7(17) 2008, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. सचिव उत्तराखण्ड, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)  
उप सचिव।